ग्रामोद्योगों की संख्या 96 है जिन्हें 7 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है जो इस प्रकार हैं :—

1. खनिज पर आधारित उद्योग ।
2. वन आधारित उद्योग ।
3. कृषि आधारित तथा खाद्य उद्योग ।
4. पॉलिमर तथा रसायन पर आधारित उद्योग ।
5. इंजीनियरी तथा गैर-परम्परा-गत ऊर्जा ।
6. वस्त्र उद्योग (खादी के अतिरिक्त) ।
7. सेवा उद्योग ।

वर्ष 1991-92 के अंत तक के. वी. आई. कार्यकलापों द्वारा दिये गये रोजगार की कुल संख्या 50.16 लाख है (खादी—14.20 लाख और ग्रामोद्योग—35.96 लाख) । महिलाओं को दिया गया रोज़गार 23.07 लाख है जो के. वी. आई. सी. द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल रोजगार का 46% है ।

(ग) सरकार के. वी. आई. सी. को उनके कार्यकलाप चलाने के लिए अपने वार्षिक बजट में निधियाँ उपलब्ध कराता है ।

के. वी. आई. सी. समय-समय पर प्रदर्शनियाँ आयोजित करके खादी तथा ग्रामोद्योग उत्पादों का विदेशों में निर्यात करने को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है ।

के. वी. आई. सी. देश में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहन दे रहा है तथा भविष्य में और केन्द्रों के खोले जाने की संभावना है ।

Administrative set up of Small-Scale Indnstries

4310. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are planning to restructure the administrative set up governing the small-scale sector,

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether Government have any plan to change the legal provision relating to small-scale industrial units?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES & AGRO AND RURAL INDUSTRIES) (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) No, Sir. However, Govt is responsive to the developmental needs of small industries and adjusts its regime of administrative systems, rules and procedures in accordance with requirements.

(b) Does not arise.

1(c) No. Sir.

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में औद्योगिक कार्यशाला

4311. श्री बलदेव प्रसाद भाखरानी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की सबसे बड़ी औद्योगिक कार्यशाला, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को भारत सरकार से कार्य नहीं मिलने का क्या कारण है;

(ख) क्या भारत सरकार बिहार के लोगों की प्रगति नहीं चाहती है; और

(ग) यदि सरकार बिहार के लोगों की प्रगति चाहती है, तो क्या वह हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची स्थित औद्योगिक कार्यशाला को समुचित सहायता देना चाहेगी ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में कम्पनी की कार्यादेश स्थिति संतोषजनक रही है, फिर भी कम्पनी को संसाधनों की कमी और कड़ी प्रतिस्पर्धा आदि जैसे अनेक कारणों से कार्यादेश की कमी का सामना करना पड़ रहा है ।

(ख) और (ग) एच. ई. सी. को योजना और गैर योजना निधियों, बैंकों में नकद उधार सीमा बढ़ाकर तथा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के कार्यान्वयन इत्यादि के द्वारा पर्याप्त सहायता प्रदान की गई है ।

Contribntory Pension by P.S.Us

4312. SHRI AJIT P. K. JOGI:
SHRI B. K. HARIPRASHAD:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the proposals of some Public Sector Undertakings for payment of contributory pension to their employees have not been considered by Government;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether some of these undertaking! have already collected funds from their employees; and

(d) if so, the names of such Public Sector Undertakings ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) and (b) The Memoranda of Understanding signed by some Public Sector Enterprises dui-